

## 3. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

### 3.1. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

## साइबर सुरक्षा – एक नज़र में



#### साइबर सुरक्षा के बारे में

- साइबर स्पेस में एकत्रित जानकारी या संपत्ति को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, बाधा, संशोधन या विनाश से सुरक्षित करने की प्रक्रिया साइबर सुरक्षा कहलाती है।
- साइबर स्पेस में लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंतर्संबंध होता है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा नेटवर्क के विश्वव्यापी वितरण द्वारा समर्थित होता है।
- भारत, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (Global Cybersecurity Index: GCI) 2020 में चीन और पाकिस्तान से आगे 10वें (194 देशों में) स्थान पर है।



#### साइबर सुरक्षा की आवश्यकता

- राष्ट्रीय सुरक्षा: कई देश (चीन सहित) साइबर हमलों में क्षमता विकसित कर रहे हैं, जो युद्ध के समय निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
- यह बांधों, आपातकालीन सेवाओं, बिजली और ऊर्जा, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के लिए आवश्यक है।
- सरकार का डिजिटल प्रयास बड़ी संख्या में नागरिकों, कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को ऑनलाइन लेनदेन हेतु प्रेरित कर रहा है।
- डिजिटल रूप से असुरक्षित लक्ष्य (1.15 बिलियन से अधिक फोन और 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता)।
- आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए (अगले 10 वर्षों में साइबर हमलों के कारण नुकसान 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है)।
- स्टार्टअप डिजिटल प्रयास (भारत डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है)।



#### साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ

- व्यापक डिजिटल निरक्षरता।
- अपर्याप्त सुरक्षा अवसंरचना वाले निम्न कोटि के उपकरणों का उपयोग।
- सुभेद्यता के बारे में जानकारी साझा करने में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का संकोच।
- अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता।
- एजेंसियों के बीच समन्वय की स्पष्ट कमी।
- पर्याप्त बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी।
- अन्य चुनौतियाँ: राज्य स्तर पर क्षमता की कमी, भौगोलिक बाधाओं का अभाव, भारत के बाहर स्थित अधिकांश सर्वर, साइबर स्पेस में तेजी से विकसित हो रही तकनीक आदि।



#### साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा तंत्र

- विधायी उपाय
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020: राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित, विश्वसनीय, लचीला और जीवंत साइबर स्पेस सुनिश्चित करना।
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013: इसका उद्देश्य साइबर स्पेस में सूचना के बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और साइबर घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है।
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: साइबर सुरक्षा के लिए डेटा एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के माध्यम से किए गए लेनदेन आदि के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- संस्थागत उपाय
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)।
  - भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)
  - राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC)।
  - रक्षा मंत्रालय ने रक्षा साइबर एजेंसी का गठन किया।
  - राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)।
  - साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर)
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल।



#### आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ोतरी: साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन को अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए।
- विभिन्न संस्थानों/एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना और साइबर सुरक्षा के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण तैयार करना चाहिए।
- बदलते साइबर परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए आई. टी. अधिनियम में संशोधन करना व साइबर सुरक्षा नीति को अपडेट करना आवश्यक है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए साइबर बीमा ढांचे और साइबर ऑडिट की स्थापना की जानी चाहिए।
- क्षमता निर्माण और कौशल विकास जरूरी है।
- साइबर संचालन के लिए तेलिन मैनुअल (Tallinn manual) जैसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना चाहिए।